



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2005/आश्विन 8, 1927

No. 1051]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2005/ASVINA 8, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2005

का.आ. 1431(अ).—यतः अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार का विचार था कि उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपने अधिकथन में भारत सरकार ने उल्लेख किया है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत "अशान्त क्षेत्र" की घोषणा करने के सम्बन्ध में सभी अद्यतन अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के अन्दर समीक्षा की जाएगी।

3. हालात की पिछली बार मार्च, 2005 में समीक्षा की गयी तथा दिनांक 31 मार्च, 2005 के का.आ. 460(अ) की अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को "अशान्त क्षेत्र" के रूप में घोषित करने की अवधि को 30 सितम्बर, 2005 तक बढ़ा दिया था। इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के ये दोनों जिले विद्रोह ग्रस्त हैं। इन दोनों जिलों में नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दोनों धड़ों की तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) की हिंसक गतिविधियाँ जारी हैं। इन दोनों जिलों को विद्रोहियों विशेषकर नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दोनों धड़ों तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) द्वारा पड़ोसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने ले जाने के लिए पारगमन मार्गों के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के इन दोनों जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह विरोधी सतत प्रचालनों और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है फिर भी केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल बरकरार रखा जाए बल्कि उन्हें तीव्र कर दिया जाए।

4. उपर्युक्त के आलोक में केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां अभी भी ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जा सकता है। अतः यह निश्चय किया गया है कि मंत्रालय द्वारा उल्लिखित दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना को 31 मार्च, 2006 तक, बशर्ते की यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड]

एच. एस. ब्रह्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2005

S.O. 1431(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in March, 2005 and *vide* Notification bearing S.O. 460(E) dated 31st March, 2005, tenure of the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2005. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The violent activities of two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) in these two districts continue. These districts are also being used as transit route by insurgents especially the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) for transshipment of arms and ammunitions from neighbouring country. Though the security situation in these two districts of Arunachal Pradesh is under control due to sustained counter-insurgency operations by the Security Forces and steps taken by the State Government, the Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

H. S. BRAHMA, Jt. Secy.